

removal of poverty as an integral part of the growth objectives of the Fifth Plan. As a result of the postulated rate and pattern of growth, the stress on a more effective population policy, the emphasis on creation of mass employment opportunities, the provision for a National Minimum Needs Programme and the envisaged public distribution system to ensure availability of essential goods to low income strata at reasonably stable prices, it is expected that the monthly per capita consumption of the poorest 30 per cent of the population would rise to the level necessary to ensure a minimum desirable consumption standard.

केन्द्र से अग्रगण्य होने की राज्यों की प्रवृत्ति

5109. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में केन्द्र से अग्रगण्य होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ;

(ख) क्या केन्द्र सभी राज्यों और कम से कम पिछड़े राज्यों की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक उन्नति के बारे में समान रूप से ध्यान नहीं दे रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या योजना बनाये जाने का प्रस्ताव है जिसमें सभी राज्यों पर समान रूप से ध्यान दिया जा सके और ऐसी प्रवृत्ति का मुकाबला किया जा सके ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहम्मिन) : (क) में (ग). सरकार को राज्यों की ऐसी प्रवृत्ति की कोई सूचना नहीं है । केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध संविधान

के उपबन्धों से नियंत्रित होते हैं । प्रशासनिक सुधार आयोजन केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि "केन्द्र और राज्यों के बीच समुचित तथा सोहार्दपूर्ण सम्बन्धों के लिए किसी संविधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाले संविधान के उपबन्ध किसी स्थिति से निपटने अथवा इस क्षेत्र में उत्पन्न किसी समस्या के समाधान के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है ।" राज्यों को केन्द्रीय सहायता का वितरण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्णयित किए गये मानदण्डों के अनुसार किया जाता है । योजनाएँ तैयार करने, विकास योजनाओं को स्वीकार करने तथा धन व्यय करने के क्षेत्र में राज्यों को यथेष्ट स्वतंत्रता है । पिछड़े राज्यों के हित में, केन्द्रीय करों में राज्यों के भाग के वितरण के बारे में वित्त आयोग उत्तरोत्तर मावधानी से विचार कर रहा है । राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के वितरण के मानदण्ड राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्णयित किये जाते हैं इसमें राज्यों के पिछड़ेपन तथा विशेष समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाता है ।

Break-downs in Atomic Power Plants

5110. SHRIMATI SAVITRI SHYAM: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1278 on 28th February, 1973 regarding setting up of atomic power houses in the country and state:

(a) the total number of break-downs in all the atomic power Plants;

(b) the causes of the break-downs; and

(c) the steps being taken to remove the defects to avoid break-downs?